औसत किस्म का होता है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है भारतीय खाद्य निगम के डिपो से दिए जाने के बाद स्टाक की जांच करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है वे यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करती हैं कि किसी कर्मचारी या बिचौलिये या उचित मूल्य की दूकानों के व्यापारियों द्वारा खाद्यान्नों में कोई मिलावट नहीं की जाती है या उन्हें घटिया स्टाक से बदला नहीं जाता है इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) and (b) AH possible efforts are made by the Food Corporation of India to check quality at the procurement stage and at the time of issue of foodgrains from the FCI depots to the State Governments and the fair price shops. The stocks so issued are of a fair average quality and conform to the specifications laid down by the Government of India. The subsequent checking of stocks, after issue from the F.C.I, depots, is the responsibility of the State Governments who make every endeavour to ensure that there is no adulteration or replacement of foodgrains by substandard stocks by any officials or middlemen or by fair price shop dealers. Any complaints received in this regard are promptly looked into.]

10+2+3 शिक्षा प्रणाली

249. **श्री गुरुदेव गुप्त :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री 30 नवम्बर, 1977 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 615 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उन राज्यों को देश में शिक्षा की सामान्य प्रणाली में सम्मिलित करने के प्रयोजन से क्या कदम उठाना चाहती है जिन्होंने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के लिए अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है; और

(ख) देश में 10+2+3 की नई शिक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन में कितना आवर्ती और अनावर्ती व्यय होने की संभावना है ?

10+2+3 educational pattern

249. SHRI GURUDEV GUPTA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 615 given in the Rajya Sabha on the 30th November, 1977 and state:

(a) what steps Government propose to take to ask those States which have not yet given their approval to the 10+2+3 pattern of education to bring them on the general pattern of education in the country; and

(b) what is the recurring and nonrecurring expenditure likely to be incurred in the implementation of the 10+2 + 3 Educational pattern in the country?]

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सभी राज्य संघ शासित क्षेत्र शिक्षा की 10+2+3 पद्धति को कार्यान्वित करने के लिए अब सिद्धान्त रूप से सहमत हो गए हैं ।

(ख) क्योंकि शिक्षा की 10+2+3 पद्धति राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी है अत: केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए हैं ।

t[THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) All States/Union Territories have since agreed in principle to implement the 10+2 + 3 pattern of education.

t[ ] English translation.

(b) Since the 10 + 2 + 3 pattern of education has to be implemented by the State Governments, no estimates have been worked out by the Central Government.]

Confirment of right and title of horn-stead and agricultural land to refugees in West Bengal

250. SHRI PRASENJIT BARMAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government have received any proposal from the West Bengal Government about confirment of right and title of homestead and agricultural lands on refugees free of cost and without any condition attached thereto; and

(b) if so, what decision Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KIN-KAR): (a) The State Government of West Bengal have suggested to Government of India the removal of the restrictive clauses of the lease-hold of 99 years on which basis urban lands were given to the displaced persons from former East Pakistan and making the terms at par with rural areas, **on a** free hold basis.

(b) The suggestions will be considered in the light of the recommendations of the Committee set up by the Ministry of Works and Housing to examine the working of lease-hold system.

देश में वनों के विनाश को रोकने के उपाय

251. **डा० लोकेश चन्द्र :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार देश में वनों का विनाश रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

Step$_s$ to check deforstation in the country

251. DR. LOKESH CHANDRA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state what steps Government propose to take to stop deforestation in the country?]

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): राष्ट्रीय वन नीति, 1952 का पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा वन क्षेत्रों के विनाश और वन भूमि को वन के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में लाने से रोकने के सुरक्षात्मक उपाय इस नई राष्ट्रीय वन नीति में सम्मिलित किए जाएंगे ।

संशोधित वन अधिनियम में, जिसका इस समय पुनरीक्षण किया जा रहा है नीति के उन उपबन्धों को लागू करने के लिए भी समुचित संशोधन किए जाने की सम्भावना है ।

वनों के विनाश से सम्बन्धित सभी मामलों की समुचित रूप से जांच-पड़ताल करने के लिए राज्यों को उचित मार्गदर्शन जारी किए जा रहे हैं तथा साथ ही साथ वनारोपण अथवा बागानों के लिए वन भूमि की इस क्षति को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने हैं । इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों की ऐसी भूमि में, अर्थात्, परती भूमि, सामुदायिक भूमि, सड़कों की दोनों किनारों की भूमि, नहरों के किनारों तथा रेल की पटरियों के दोनों ओर की भूमि में सामाजिक वानिकीकार्यक्रमों को भी तेज किया जाएगा ।

f[THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): The National Forest Policy 1952 is under revision and suitable safeguards for checking deforestation of forest areas and diversion of forestry lands to non-